आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 08.04.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों को बधाई दी, कहा– इस योजना ने सपनों को हकीकत में बदल दिया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेतु आयोग को राज्य की गोल्डन जुबली– 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा – चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेशभर में एक से 19 वर्ष तक के 36 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाई जा रही ळें

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। अप्रैल 2015 में शुरू की गई इस प्रमुख योजना के दस साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि कैसे इस योजना ने सपनों को हकीकत में बदलकर जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने उन लोगों को सशक्त बनाया है, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था और इस बात पर जोर दिया कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना अनगिनत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें अपने उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है, ताकि वे केवल नौकरी चाहने वाले न होकर नौकरी देने वाले बन सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा ऋण लाभार्थियों में से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और उनमें से लगभग आधी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। उन्होंने प्रत्येक मुद्रा ऋण को गरिमा, आत्म–सम्मान और अवसर का प्रतीक बताया। बातचीत के दौरान, लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने उद्यमशीलता के अनुभव साझा किए।

सेतु आयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेतु आयोग को राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग द्वारा 02 वर्ष का अल्पकालिक, 10 वर्ष का मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। योजना बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने अब तक आयोग द्वारा किए गए और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित और सशक्त उत्तराखंड की दृष्टि से राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए विभागों के साथ समन्वय कर उन नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना सेतु आयोग का मुख्य उद्देश्य है।

चारधाम स्वास्थ्य सुविधा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को यात्राकाल का ठोस रोडमैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर तैनात आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट करने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली चिकित्सा इकाईयों और चारों धामों में विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब जाने वाले पैदल यात्रियों की सुविधा के लिये बनाये गये मेडिकल रिस्पांस प्वाइंट की संख्या बढ़ाने के साथ ही मेडिकल स्टॉफ को आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने को कहा। डॉ. रावत ने बताया कि बैठक में चार धाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत इस वर्ष 49 स्थाई चिकित्सा इकाईयों के साथ ही 25 अस्थाई चिकित्सा इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें रोटेशन के आधार पर विशेष चिकित्सकों और चिकित्साधिकारियों के साथ ही पैरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती की जायेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा रूटों पर कुल 154 एम्बुलैंस तैनात की जायेंगी। इसके अलावा यात्रा के दौरान एक हेली एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को एयर लिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश अथवा दून मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जा सके।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत आज से प्रदेशभर में एक से 19 वर्ष तक के 36 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाई जा रही है। सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य शिक्षा अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं, देहरादून में इस अवसर पर सचिवालय के निकट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड की निदेशक स्वाति एस. भदौरिया ने की। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान भी मौजूद रहीं। पत्रकारों से बातचीत में मिशन निदेशक स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है।

दवा से वंचित रह जाने वाले बच्चों को 16 अप्रैल को होने वाले मॉप अप दिवस पर अनिवार्य रूप से कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी।

बीकेटीसी

बदरी–केदार मंदिर समिति– बीकेटीसी का तीस सदस्यीय अग्रिम दल श्री बदरीनाथ धाम पहुंच गया है। इस दल में मंदिर के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक और 15 मजदूर शामिल हैं। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि मंदिर समिति का अग्रिम दल बदरीनाथ धाम में मंदिर समिति के विश्रामगृहों, कार्यालयों, विभिन्न पूजा काउंटरों, दर्शन पंक्ति, स्वागत कार्यालय, सौंदर्यीकरण कार्य, विद्युत, पेयजल और साफ–सफाई सहित मरम्मत कार्य करेगा। वहीं, 10 अप्रैल के बाद मंदिर समिति का अग्रिम दल केदारनाथ के लिए भी प्रस्थान करेगा। गौरतलब है कि बदरीनाथ धाम के कपाट 04 मई को खुल रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बीकेटीसी के स्तर से भी यात्रा की तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही हैं।

शोध कार्य

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समक्ष उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी ने राजभवन में 'वन यूनिवर्सिटी–वन रिसर्च' के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। विश्वविद्यालय की ओर से ''उत्तराखण्ड में दिव्यांग, शोषित और वंचितों के लिए शिक्षा जागरूकता'' विषय पर शोध किया जा रहा है। प्रोफेसर नेगी ने बताया कि शोध का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले दिव्यांगजनों, शोषित और वंचित समुदायों तक शिक्षा की पहुँच, अवसरों और समावेशी नीतियों का मूल्यांकन करना है। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकत्री, आंगनबाड़ी और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से लक्षित समूहों की पहचान कर उन्हें विशेष शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह शोध समाज के उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो किन्हीं कारणों से शिक्षा लेने से वंचित हो गए थे। राज्यपाल ने कुलपति को निर्देश दिए कि इस शोध को और अधिक व्यापक, गहन और व्यावहारिक बनाएं, ताकि इसके निष्कर्ष नीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हों।